राजस्थान अंतरिम बजट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी**, जो राज्य के दो उप मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, ने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया।

मुख्य बिंदु:

- राज्य के वित्त मंत्री ने विधानसभा क्षेत्रों में **स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना, उन्नयन के लिये 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की** । उन्होंने मज़दूरों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की भी घोषणा की।
- बजट में **मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान-2** की भी घोषणा की गई, जिसमें **11,200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ अगले चार वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाएँ** बनाने की योजना है।
- बजट में रिक्त पदों को भरने और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये विभिन्न विभागों में **70,000 पदों** पर भर्ती करने का प्रस्ताव है।

अंतरिम बजट

- अंतरिम बजट **एक ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो संक्रमण काल से गुज़र रही है या आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष** में है।
- अंतरिम बजट का उद्देश्य सरकारी व्यय और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है जब तक कि नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद **पूर्ण बजट** प्रस्तुत न कर दे।

लेखानुदान

- लेखानुदान, जैसा कि भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 116** द्वारा परिभाषित है, केंद्र सरकार के लिये भारत की संचित निधि से **अल्पकालिक व्यय आवश्यकताओं** को पूरा करने हेतु **अग्रिम अनुदान** है, जो आम तौर पर नए वित्तीय वर्ष तक कुछ महीनों तक चलता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-interim-budget